रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052020-219645 CG-DL-E-29052020-219645

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1509] No. 1509] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 28, 2020/ज्येष्ठ 7, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 28, 2020/JYAISHTHA 7, 1942

## श्रम और रोजगार मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2020

**का.आ. 1679(अ).**— भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने तारीख 13 अगस्त, 2019 की अधिसूचना का.आ. संख्यांक 2927 (अ) द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, भारत की पूर्व सचिव, श्रीमती रिश्म वर्मा को मैसर्स ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के खुली कास्ट खदान, राजमहल, झारखंड राज्य के जिला गोड्डा में हुई बड़ी दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच पड़ताल करने और तीन माह की अविध के भीतर अर्थात् 12 नवम्बर, 2019 तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया था;

और, उक्त जांच न्यायालय को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि तारीख 13 नवम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 4081(अ) द्वारा तीन माह की अतिरिक्त अवधि के लिए अर्थात्, 12 फरवरी, 2020 तक बढ़ाई गई थी और 17 फरवरी, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 740 (अ) द्वारा तीन माह की अतिरिक्त अवधि के लिए अर्थात्, 12 मई, 2020 तक भी बढ़ाई गई थी;

और, तीन माह की बढ़ाई गई अवधि 12 मई, 2020 को समाप्त हो गई;

और, पूर्वोक्त अवधि के दौरान जांच न्यायालय ने अपनी जांच में काफी प्रगति की है और जांच की कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत गवाहों और अनेक दस्तवेजों की जांच करने के लिए अब भी और अधिक समय अपेक्षित है;

और, 27 फरवरी, 2020 तक पंद्रह बैठकों का आयोजन किया जा चुका है और 50 व्यक्तियों ने अभिसाक्ष्य दिया तथा उनकी परीक्षा की तथा कार्यवाहियों के दौरान 1200 पृष्ठ निर्देशित किए;

2294 GI/2020 (1)

और, 27 फरवरी, 2020 की बैठक में न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम वर्धमान जिले के कुनुस्तोरिया क्षेत्र पर 24 से 26 मार्च 2020 तक अपनी बैठकों का आयोजन करने का विनिश्चय किया। संबंधित व्यक्तियों को समन, नोटिस और जानकारी दी गई थी;

और, कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण न्यायालय की बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सका;

और, अवधि को बढ़ाना आवश्यक हो गया है जिसमें जांच की जानी है तथा अतिरिक्त सुरक्षा उपायों या उपचारात्मक उपायों, सिफारिश यदि कोई हो, को किया जाना है और रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाना है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, इस अवधि को 13 मई, 2020 से 12 अगस्त, 2020 तक तीन माह की अतिरिक्त अवधि के लिए या उस दिन या उस तारीख जिसको जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाती है। तद्नुसार, जांच करने और अतिरिक्त सुरक्षा उपायों या उपचारात्मक उपायों, सिफारिश के लिए, यदि कोई है और रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष श्रीमित रिश्म वर्मा, पूर्व सचिव, भारत सरकार तथा एसेसर के रूप में श्री अख्तर जावेद उस्मानी, हिन्द मजदूर सभा के प्रतिनिधि और श्री रवीन्द्र शर्मा, पूर्व मुख्य खान निरीक्षक और डीजीएमएस की नियुक्ति 13 मई, 2020 से 12 अगस्त, 2020 की अवधि तक या उस दिन या उस तारीख जिसको जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

[फा. सं. एन-11012/3/2016-आईएसएच-॥]

कल्पना राजसिंहोत, सयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2020

**S.O.** 1679(E).—Whereas the Government of India in the Ministry of Labour and Employment *vide* their notification number S.O. 2927(E), dated 13<sup>th</sup> August, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) appointed Smt. Rashmi Verma, Former Secretary to the Government of India to go into causes and circumstances of the major accident which occurred on 29<sup>th</sup> December, 2016 at Rajmahal Opencast Mines of M/s. Eastern Coal Fields Limited in District Godda of Jharkhand State and to make recommendations, if any, for further safety steps or remedial measures required to be taken, ought to be held and present a report within a period of three months, i.e., upto 12<sup>th</sup>November, 2019;

And whereas to accomplish the tasks assigned to the said Court of Inquiry and to submit a report the duration was extended for a further period of three months, i.e., upto 12<sup>th</sup> February, 2020 *vide* notification number S.O. 4081(E), dated the 13<sup>th</sup> November, 2019, and also for a further period of three months, i.e., upto 12<sup>th</sup> May, 2020 *vide* notification number S.O. 740(E), dated the 17<sup>th</sup>February, 2020;

And whereas the extended period of three months came to an end on 12<sup>th</sup>May, 2020;

And whereas during the aforesaid period the Court of Inquiry made a considerable progress in its enquiry and still require further more time to examine the witnesses and several documents submitted during the course of inquiry;

And whereas till 27<sup>th</sup> February, 2020, fifteen number of sittings have been held and 50 persons were deposed and examined and around 1200 pages of documents were referred to in the course of proceedings;

And whereas on 27<sup>th</sup> February, 2020 sitting, the Court decided to hold its sittings from 24<sup>th</sup> to 26<sup>th</sup> March, 2020 at Kunustoria Area, Paschim Bardhaman District of West Bengal State, summons and notices and information had been given to the concerned persons;

And whereas due to nationwide lockdown in view of outbreak of COVID-2019 pandemic the sittings of the Court could not be held;

And whereas it has become necessary to extend the period with in which the inquiry is to be conducted, and, recommendations, if any, for further safety steps or remedial measures is to be made and report presented;

Now, therefore, to give continuity to the aforesaid Court of Inquiry, the Central Government do hereby extend the duration for a further period of three months from 13<sup>th</sup> May, 2020 to 12<sup>th</sup> August, 2020 or till the day or date on which the report of the inquiry is submitted, whichever is earlier. Accordingly, the period of appointment of Chairperson Smt. Rashmi Verma, Former Secretary to the Government of India to conduct the inquiry, and, to make recommendations, if any, for further safety steps or remedial measures and present the report and the period of Shri Akhter Javed Usmanee, representative of Hind Mazdoor Sabha and Shri Rabindra Sharma, ExChief Inspector of Mines and DGMS, as assessors is also extended for a further period of three months from 13<sup>th</sup> May, 2020 to 12<sup>th</sup> August, 2020 or till the day or date on which the report of the inquiry is submitted, whichever is earlier.

[F. No. N-11012/3/2016-ISH.II] KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.